Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged portrayal of high grade iron ore as low grade by private miners in Odisha

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज मैं ओडिशा राज्य के मिनरल माइनिंग सेक्टर (खनिज खनन क्षेत्र) में हो रही व्यापक अनिमितता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । ओडिशा राज्य में आर्थिक वर्ष 2020-21 में बहुत सारे आयरन ओर माइन्स राज्य सरकार द्वारा नीलाम किए गए थे । बहुत आश्चर्य की बात है कि तुरंत आर्थिक वर्ष 2021-22 से नए नीलामधारियों ने खनन किए गए आयरन ओर में लो ग्रेड आयरन ओर का परिमाण बहुत अधिक दिखलाना शुरू कर दिया ।

सर, मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगी । हम सब जानते हैं कि 55 प्रतिशत फेरस कंटेंट से कम वाले आयरन ओर को हम लो ग्रेड आयरन ओर कहते हैं और इसका मूल्य बहुत कम होता है । आर्थिक वर्ष 2019-20, यानी माइन्स नीलाम होने से पहले लो ग्रेड आयरन ओर का प्रतिशत इन माइन्स में 0.9 प्रतिशत था । एक वर्ष के अंदर इन नए नीलामधारियों ने इस 0.9 परसेंट को 27.3 परसेंट दिखलाया कि लो ग्रेड आयरन ओर इतना बढ़ गया ।

सर, 20-30 सालों से जिन माइन्स में हाई ग्रेड आयरन ओर होता था, वहां वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बढ़कर 27.3 प्रतिशत हो गया । अप्रैल, 2022 और मई, 2022 में यह प्रतिशत बढ़कर 42.3 प्रतिशत और 58.9 प्रतिशत हुआ । इससे यह हुआ कि एवरेज सेल प्राइस कम हो गया, बिड अमाउण्ट कम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड में कम पैसे आने लगे और राजकोष को करोड़ों का नुकसान हुआ तथा जनकल्याणकारी कार्य दुर्भाग्यवश बुरी तरह से प्रभावित हुए । इसमें बड़ी बात यह है कि मेरे हाथ में एक पत्र है । इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स ने सरकार को लिखा और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा । यह चिट्ठी दिनांक 11.08.2022 की है ।

इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार ओडिशा को तुरंत लिखा जाए और तदर्थ किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए एवं इंवेस्टिगेशन हो, रिपोर्ट मांगी गई, तलब की गई, लेकिन ओडिशा राज्य सरकार ने कर्णपात नहीं किया । अभी तक किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं हुई है और इससे राजकोष को बहुत नुकसान पहुंचा है । यह दु:ख की बात है कि जनकल्याणकारी कार्य बहुत कम संख्या में हो रहे हैं ।

सर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि ओडिशा राज्य एक गरीब प्रदेश है, उसकी जनता प्रभावित हो रही है, तो मैं आपके दरख्वास्त करना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार तुरंत राज्य सरकार से फिर से रिपोर्ट मांगे, इंक्वायरी हो और इस दिशा में सुधार लाया जाए ।